ओम प्रकाश

बनाम

राजस्थान राज्य और अन्य

(2012 की आपराधिक अपील सं. 651)

13 अप्रैल, 2012

[जी. एस. सिंघवी और ज्ञान सुधा मिश्रा, जे. जे.]

किशोर न्यायाधीश (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2000-बलात्कार का अपराध-आरोपी द्वारा किशोरता की याचिका-आरोपी की उम्र का निर्धारण-चिकित्सा साक्ष्य-13 प्रतिशत लड़की की प्रशंसा जो कथित रूप से आरोपी-प्रतिवादी सं.2 और एक सह-अभियुक्त-प्रतिवादी नं।2 किशोर होने का दावा किया गया ~ निचली अदालत और उच्च निचली अदालत दोनों इस तथ्य का निर्णायक निष्कर्ष दर्ज नहीं कर सके कि प्रतिवादी नहीं।2 घटना की तारीख को वह एक किशोर था, फिर भी उसे किशोर न्यायाधीशालय में मुकदमे के लिए भेजने के लिए किशोर न्यायाधीश अधिनियम का लाभ दिया गया-पीड़ित के पिता की अपील पर, उसने कहाःअभियुक्त-प्रतिवादी की आयु सं।2 इसे केवल स्कूल रिकॉर्ड के आधार पर साबित नहीं किया जा सका क्योंकि निचली अदालतें अपनी जांच के बावजूद इस तथ्य को दर्ज नहीं कर सकीं कि आरोपी वास्तव में घटना की तारीख को नाबालिग था-ऐसी स्थिति में जब स्कूल रिकॉर्ड ही अस्पष्टता से मुक्त नहीं है, तो चिकित्सा राय को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है या कोई परिणाम नहीं माना जा सकता है-आरोपी के एक्स-रे और ऑसिफिकेशन परीक्षण के आधार पर चिकित्सा विशेषज्ञों की राय को स्कूल के रिकॉर्ड के आधार पर अस्थिर साक्ष्य और आरोपी के पिता द्वारा स्थापित एक कहानी के आधार पर परिस्थितिजन्य निष्कर्ष की याचिका पर प्राथमिकता देनी होगी-जबकि ऑसिफिकेशन परीक्षण करने वाले

चिकित्सा विशेषज्ञ ने कहा कि आरोपी की आयु घटना की तारीख को 19 वर्ष थी।

हालाँकि, स्थिति अलग होगी यदि कथित किशोर की उम्र को छिपाने के लिए विद्या सम्बन्धी रिकॉर्ड को जानबूझकर रोक दिया गया है और अभियोजन पक्ष के कहने पर चिकित्सा साक्ष्य की प्रामाणिकता को चुनौती दी गई है-उस स्थिति में, क्या चिकित्सा साक्ष्य पर भरोसा किया जाना चाहिए या नहीं, यह प्रतिद्वंद्वी पक्षों के नेतृत्व वाले साक्ष्य के मूल्य पर निर्भर करेगा-प्रतिवादी नं 2 और उसके पिता यह साबित करने में विफल रहे कि प्रतिवादी नं 2 अपराध के समय नाबालिग था-हालाँकि किशोर न्यायाधीश अधिनियम अपने आप में एक परोपकारी कानून है, लेकिन इसके तहत सुरक्षा किसी ऐसे आरोपी को उपलब्ध नहीं कराई जा सकती है जो वास्तव में किशोर नहीं है, लेकिन केवल एक सुरक्षात्मक छत्र या वैधानिक ढाल के रूप में इसका उपयोग करके आश्रय चाहता है-नतीजतन, अभियुक्त-प्रतिवादी नं 2 सक्षम अधिकार क्षेत्र की अदालत के समक्ष मुकदमे के लिए भेजे जाने का निर्देश दिया गया, जिसमें मुकदमा लंबित है और किशोर न्यायालय के लिए नहीं, जैसा कि उसके द्वारा अनुरोध किया गया है-चिकित्सा न्यायशास्त्र।

अपीलकर्ता एक 13 प्रतिशत वर्ष की लड़की का पिता है जिसका अभियुक्त-प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा कथित रूप से बलात्कार किया गया था।उत्तरदाता नं.2 किशोर न्यायाधीश (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम 2000 के तहत सुरक्षा का लाभ उठाने की अनुमति दी गई थी, हालांकि नीचे की अदालतें यह निष्कर्ष दर्ज नहीं कर सकीं कि वह वास्तव में घटना की तारीख को एक किशोर था।

तत्काल अपील अन्य बातों के साथ साथ विचार के लिए जो प्रश्न उठे थे, वे थेः- (□) क्या प्रतिवादी/आरोपी, जिस पर भा.दं.सं. सी. की खंड 376 और अन्य संबद्ध खंडओं के तहत बलात्कार का अपराध आदेशने का आरोप है, के साथ-साथ एक सह-

आरोपी, जो पहले से ही भा.दं.सं. सी. की खंड 376 के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है, को किशोर न्यायाधीश (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2000 के तहत किशोर अदालत में मुकदमे के लिए भेजने के लिए सुरक्षा का लाभ उठाने की अनुमति दी जा सकती है, हालांकि निचली अदालत और उच्च निचली अदालत इस तथ्य का विद्या सम्बन्धी निष्आदेशष दर्ज नहीं आदेश सके कि प्रतिवादी-आरोपी घटना की तारीख को 18 वर्ष से कम उम्र का था; (ii) क्या किशोर न्यायाधीश अधिनियम से संबंधित 'परोपकारी कानून' का सिद्धांत और लाभ उन मामलों में लागू किया जा सकता है जहां निर्धारण के संबंध में दो विचार हैं।

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया

1. तत्काल मामले में, अभियुक्त की आयु-प्रतिवादी सं 2 इसे केवल स्कूल रिकॉर्ड के आधार पर साबित नहीं किया जा सका क्योंकि निचली अदालतें अपनी जांच के बावजूद इस तथ्य का निष्कर्ष दर्ज नहीं कर सकीं कि आरोपी वास्तव में घटना की तारीख को नाबालिग था।ऐसी स्थिति में जब स्कूल रिकॉर्ड स्वयं अस्पष्टता से मुक्त नहीं है और निर्णायक रूप से अभियुक्त-प्रतिवादी नं.2, चिकित्सकीय राय को अनदेखा या अनुपयुक्त नहीं होने दिया जा सकता है। इस संदर्भ में एन. ए. डब्ल्यू.-3, चिकित्सा न्यायविद, जिन्होंने अभियुक्त का अस्थिकरण परीक्षण किया और अदालत के समक्ष यह राय दी कि अभियुक्त की आयु 19 वर्ष थी, का बयान महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें विशेष रूप से कहा गया है कि अभियुक्त अपराध करने की तारीख को किशोर नहीं था। एन. ए. डब्ल्यू.-1, सहायक का वक्तव्य रेडियोलॉजी के प्रोफेसर को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है क्योंकि उनकी राय है कि एक्स-रे फिल्मों के आधार पर आरोपी की उम्र 18 वर्ष से अधिक और 20 वर्ष से कम है।इस प्रकार, ऐसी परिस्थिति में जहां निचली निचली अदालत स्वयं आरोपी की उम्र के संबंध में एक निर्णायक निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकी, एक्स-रे और ऑसिफिकेशन परीक्षण के आधार पर चिकित्सा विशेषज्ञों की राय

को स्कूल के रिकॉर्ड के आधार पर अस्थिर साक्ष्य और आरोपी के पिता द्वारा स्थापित एक कहानी के आधार पर परिस्थितिजन्य निष्कर्ष की याचिका पर प्राथमिकता देनी होगी, जो प्रथमदृष्टया एक मुर्गा और बैल की कहानी है। [पैरा 17] [253-एफ-एच; 254-ए-डी]

2. इसमें कोई संदेह नहीं है कि यदि किशोर अभियुक्त के पक्ष में कोई स्पष्ट और स्पष्ट मामला है कि वह 18 वर्ष की आयु से कम का नाबालिग था। घटना और दस्तावेजी साक्ष्य कम से कम प्रथमदृष्टया यही साबित करते हैं, वह किशोर न्यायाधीश अधिनियम के तहत इस विशेष सुरक्षा का हकदार होगा। लेकिन जब कोई अभियुक्त एक गंभीर और जघन्य अपराध करता है और उसके बाद नाबालिग होने की आड़ में वैधानिक शरण लेने का प्रयास करता है, तो एक आकस्मिक या घुड़सवार दृष्टिकोण यह दर्ज करते हुए कि क्या कोई अभियुक्त किशोर है या नहीं, इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती क्योंकि अदालतों को न्यायाधीश के प्रशासन को सौंपे गए संस्थान में आम आदमी के विश्वास की रक्षा करने के उद्देश्य से अपने कर्तव्यों का पालन करने का आदेश दिया गया है। इसलिए, जबकि अदालतों को यौन उत्पीड़न, बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, हत्या और अन्य अपराधों जैसे गंभीर प्रकृति के मामलों में शामिल किशोर से निपटने में संवेदनशील होना चाहिए, आरोपी को खुद को साबित करने का प्रयास करके वैधानिक संरक्षण का दुरुपयोग करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। जब उसके अल्पमत को साबित करने के लिए दस्तावेजी साक्ष्य उसके अल्पमत के दावे के बारे में एक उचित संदेह को जन्म देता है। ऐसी स्थिति में, वैज्ञानिक जांच के आधार पर चिकित्सा साक्ष्य को स्कूल प्रशासन के रिकॉर्ड के आधार पर साक्ष्य पर उचित महत्व और प्राथमिकता देनी होगी। अभियुक्त की आयु के बारे में परिकल्पना और अटकलों को जन्म देना।[पैरा 18] [254-डी-एच; 255-ए]

3. तत्काल मामले में, अभियुक्त-प्रतिवादी नं.2 आरोप लगाया जाता है कि उसने एक ऐसा अपराध किया है जो नैतिक विवेक के खिलाफ है क्योंकि उसने अपने साथी की सहायता से एक साजिश रचकर अपनी वासना को संतुष्ट करने के लिए साढ़े 13 साल की एक लड़की को चुना है, जो पहले से ही दोषी है और उसके बाद आरोपी ने इस याचिका के तहत सुरक्षा लेने का प्रयास किया है कि उसने अपनी बेगुनाही के कारण ऐसा कार्य किया है, इसके निहितार्थ को समझे बिना जिसमें उसके पिता स्पष्ट रूप से एक कहानी को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं कि वह घटना की तारीख को नाबालिग था, जो विश्वास के योग्य निर्णायक सबूत पर आधारित नहीं है, बल्कि एक भ्रमित कहानी के साथ-साथ साक्ष्य की अस्थिर और नाजुक प्रकृति पर आधारित है जो शायद ही विश्वास को प्रेरित करती है।यह नजरअंदाज करना कठिन है कि जब अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य की सावधानीपूर्वक जांच के बावजूद इस निर्णायक निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सके कि वह घटना की तारीख को स्पष्ट रूप से 18 वर्ष से कम आयु का किशोर था, तो उसे किस तर्क और तर्क से इसका लाभ मिलना चाहिए। किशोर न्यायाधीश अधिनियम के आधार पर परोपकारी विधान के सिद्धांत को समझना मुश्किल है क्योंकि यह स्पष्ट रूप से इस सिद्धांत के गलत अनुप्रयोग में परिणाम देता है और इस प्रकार अपीलकर्ता के तर्क में पर्याप्त बल है कि परोपकारी विधान के सिद्धांत का लाभ केवल उन अपराधियों के पक्ष में लागू किया जा सकता है जिन्हें निस्संदेह किशोर माना गया है जो कथित अभियुक्त की उम्र के बारे में अटकलों के लिए कोई गुंजाइश नहीं छोड़ते हैं।[पैरा 19] [255-सी-जी]

4. इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है कि निचली अदालत के साथ-साथ उच्च निचली अदालत भी विवादित आदेश पारित करते समय किसी भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सके कि क्या आरोपी घटना की तारीख को एक बड़ा या नाबालिग था और फिर भी एक आरोपी को परोपकारी कानून के सिद्धांत का लाभ देता

था, जिसकी अल्पमत की याचिका कि वह 18 वर्ष से कम आयु का था, संदेह में था। ऐसी स्थिति में, किशोरता की याचिका के समर्थन में एक विश्वसनीय और ठोस सबूत के लिए जोर देकर न्यायाधीश के तराजू को एक समान आधार पर रखने की आवश्यकता होती है, विशेष रूप से जब पीड़ित भी नाबालिग था।[पैरा 20] [255-एच; 256-ए-बी]

5. इस प्रकार किशोर न्यायाधीश अधिनियम से जुड़े परोपकारी विधान के सिद्धांत का लाभ केवल ऐसे मामलों पर लागू होगा जिसमें अभियुक्त को कम से कम अपने अल्पमत के संबंध में प्रथमदृष्टया साक्ष्य के आधार पर किशोर माना जाता है, जो कथित अभियुक्त की उम्र के संबंध में दो विचारों की संभावनाओं के लाभ के रूप में है जो गंभीर और गंभीर अपराध में शामिल है जो उसने किया और इसे निर्दोषता के बजाय अपनी मानसिक परिपक्वता को दर्शाते हुए सुनियोजित तरीके से लागू किया, यह दर्शाता है कि उसका किशोरता का अनुरोध कानून के हथियारों को चकमा देने या धोखा देने के लिए ढाल के रूप में अधिक है, उसे उसके बचाव में आने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।इसलिए यदि किशोरावस्था की याचिका या यह तथ्य कि उसने अपने जघन्य कृत्य के परिणाम को समझने के लिए विवेकाधिकार की आयु प्राप्त नहीं की थी, अस्पष्टता या संदेह से मुक्त नहीं है, तो उक्त याचिका को केवल संदिग्ध स्कूल प्रवेश रिकॉर्ड पर उठाए जाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है और यदि यह संदिग्ध है, तो आरोपी की आयु निर्धारित करते समय चिकित्सा साक्ष्य को उचित महत्व देना होगा। [पैरा 21] [256 - सी-ई]

6. इस मामले के तथ्यों में, अभियुक्त की ओर से दिए गए साक्ष्य के बावजूद, निचली निचली अदालत खुद इस बात से संतुष्ट नहीं थी कि अभियुक्त एक किशोर था क्योंकि प्रत्यर्थी-अभियुक्त द्वारा स्कूल के किसी भी रिकॉर्ड पर भरोसा नहीं किया गया था,

जिसे संदेह से मुक्त माना जा सकता था ताकि अभियुक्त की सही जन्म तिथि तय करने के उद्देश्य से एक तार्किक और कानूनी आधार बनाया जा सके जो यह दर्शाता है कि अभियुक्त घटना की तारीख को नाबालिग/किशोर था।जहां न्यायालय अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के बावजूद स्पष्ट रूप से निष्आदेशष नहीं निकाल सकते हैं कि अभियुक्त एक किशोर है या उक्त याचिका केवल एक धुंध या धुँआ पर्दा बनाने के लिए उठाई गई प्रतीत होती है ताकि उसकी वास्तविक उम्र को छिपाया जा सके ताकि अभियुक्त को उसके अल्पसंख्यक के अनुरोध पर बचाया जा सके, न्यायाधीश के उद्देश्य को नष्ट करने या धोखा देने के प्रयास को सफल नहीं होने दिया जा सकता है।अल्पमत की याचिका और बहाना की याचिका के बीच समानांतर रेखा खींचते हुए, यह हो सकता है यह कहना सार्थक है कि आपराधिक मामलों का सामना करना असामान्य नहीं है जिसमें एक आरोपी बहाना की याचिका के तहत बहाना लेने का प्रयास करता है जिसे करना पड़ता है। पहली बार में उठाया जाना चाहिए, लेकिन अपराध की सुनवाई करने वाली अदालत द्वारा साक्ष्य के सख्त सबूत के अधीन होना चाहिए और केवल इस हितकारी सिद्धांत की सहायता से सबूत की कमी के बावजूद हल्के में अनुमति नहीं दी जा सकती है कि एक निर्दोष व्यक्ति को उसकी बहाना की याचिका के बावजूद दोषसिद्धि का आदेश दर्ज करके अन्याय नहीं सहना पड़ सकता है। इसी तरह, यदि किसी अभियुक्त का आचरण या विधि और तरीका अपराध करना अपराध करने वाले अभियुक्त की एक बुरी और सुनियोजित योजना को इंगित करता है जो अपराध के परिपक्व कौशल की ओर अधिक इंगित करता है। एक निर्दोष बच्चे की तुलना में अभियुक्त, फिर अभियुक्त की उम्र के समर्थन में विश्वसनीय दस्तावेजी साक्ष्य की अनुपस्थिति में में, यह दर्शाने वाले चिकित्सा साक्ष्य कि अभियुक्त एक वयस्क था, को किशोर न्यायाधीश अधिनियम जैसे परोपकारी कानून के सिद्धांत की शरण लेते हुए नजरअंदाज करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, क्योंकि किशोर न्यायाधीश अधिनियम का वैधानिक संरक्षण उन

नाबालिगों के लिए है जो निर्दोष कानून तोड़ने वाले हैं और परिपक्व दिमाग के आरोपी नहीं हैं जो अभियुक्त की याचिका का उपयोग करते हैं। अपने द्वारा किए गए अपराध की सजा से खुद को बचाने के लिए एक चाल या ढाल के रूप में अल्पसंख्यक।किशोर न्यायाधीश अधिनियम के तहत परोपकारी कानून का लाभ स्पष्ट रूप से एक वास्तविक बाल आरोपी/किशोर को सुरक्षा प्रदान करेगा जो अदालत को इस दुविधा में नहीं डालता है कि वह नाबालिग है या नहीं, अपने अल्पमत की याचिका के समर्थन में सबूत पेश करके, लेकिन इसकी अनुपस्थिति में में, केवल स्कूल प्रवेश रजिस्टर जैसे अस्थिर साक्ष्य पर भरोसा किया जाता है जो साबित नहीं होता है या मौखिक साक्ष्य आधारित सी. एन. अनुमान जो आगे अस्पष्टता की ओर ले जाते हैं, आरोपी की उम्र का आकलन करने के लिए चिकित्सा साक्ष्य की वरीयता में भरोसा नहीं किया जा सकता है।{पारस 22,23] [256-एफ-जी; 258-बी-एच; 259-ए-बी]

7. चिकित्सीय साक्ष्य की प्रासंगिकता और मूल्य पर विचार करते हुए, आयु का चिकित्सक का अनुमान हालांकि प्रमाण के लिए एक मजबूत पदार्थ नहीं है क्योंकि यह केवल एक महत्वपूर्ण तथ्य है। राय में, ऑसिफिकेशन और रेडियोलॉजिकल परीक्षा जैसे वैज्ञानिक चिकित्सा परीक्षण के आधार पर ऐसी राय को कथित किशोर आरोपी की उम्र का निर्धारण करते समय एक मजबूत सबूत के रूप में माना जाना चाहिए। हालाँकि, स्थिति अलग होगी यदि कथित किशोर की उम्र को छिपाने के लिए विद्या सम्बन्धी रिकॉर्ड को जानबूझकर रोक दिया गया है और अभियोजन पक्ष के कहने पर चिकित्सा साक्ष्य की प्रामाणिकता को चुनौती दी गई है।उस स्थिति में, चिकित्सा साक्ष्य पर भरोसा किया जाना चाहिए या नहीं, यह स्पष्ट रूप से प्रतिद्वंद्वी पक्षों द्वारा दिए गए साक्ष्य के मूल्य पर निर्भर करेगा। [पैरा 24] [259-सी-डी-एफ-एच]

रामदेव चौहान @राज नाथ बनाम असम राज्य (2001) 5 एससीसी 714:2001 (3) एससीआर 669-पर निर्भर।

8. प्रत्यर्थी संख्या 2 और उसके पिता यह साबित करने में विफल रहे हैं कि प्रत्यर्थी संख्या 2 अपराध करने के समय नाबालिग था और इसलिए उसे किशोर न्यायाधीश अधिनियम का लाभ नहीं दिया जा सकता था, जो निस्संदेह एक हितकारी कानून है, लेकिन एक आरोपी द्वारा इसका लाभ उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, जिसने किशोरता का लाभ केवल अपनी वास्तविक उम्र को छिपाने के प्रयास के रूप में लिया है ताकि निचली अदालतों के मन में संदेह पैदा किया जा सके, जिन्होंने उसे लाभ देना उचित समझा। केवल परोपकारी विधान के सिद्धांत को अपनाकर, लेकिन इसके महत्वपूर्ण निहितार्थ को छोड़ते हुए कि यद्यपि किशोर न्यायाधीश अधिनियम अपने आप में एक परोपकारी विधान है, इसके तहत सुरक्षा एक ऐसे अभियुक्त को उपलब्ध नहीं कराई जा सकती है जो वास्तव में किशोर नहीं है, बल्कि केवल एक सुरक्षात्मक छत्र या वैधानिक ढाल के रूप में इसका उपयोग करके आश्रय चाहता है।यदि अभिलेख पर साक्ष्य और अन्य सामग्री यह साबित करने में विफल रहती है कि अपराध करने के समय अभियुक्त किशोर था तो इसे हतोत्साहित करना होगा।किशोर न्यायाधीश अधिनियम, जो निश्चित रूप से एक आरोपी बच्चे के साथ देखभाल और संवेदनशीलता के साथ व्यवहार करने के लिए है, जो उसे समाज की मुख्यधारा में सुधार करने और बसने का मौका देता है, इसे जघन्य अपराधों के मुकदमे और उपचार का संचालन करते समय न्यायाधीश के पाठ्यक्रम को धोखा देने के लिए एक चाल के रूप में इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। इसे स्पष्ट रूप से न्यायाधीश व्यवस्था को कमजोर करने के प्रयास के रूप में माना जाएगा और इसलिए इसे प्रोत्साहित नहीं किया जा सकता है। [पैरा 25] [260-ए-एफ]

10. इसलिए यह न्यायालय उच्च न्यायालय और नीचे की अदालतों द्वारा पारित निर्णय और आदेश को दरकिनार करना उचित और उचित समझता है।नतीजतन, अभियुक्त-प्रतिवादी नं।2 सक्षम अधिकार क्षेत्र के न्यायालय के समक्ष परीक्षण के लिए

भेजा जाएगा, जिसमें परीक्षण लंबित है, न कि किशोर न्यायालय में, जैसा कि उसने अनुरोध किया है। [पैरा 26] [260-एफ-जी]

मामला कानून संदर्भः

2001 (3) एस सी आर 669	संदर्भित किया	पैरा 22,24

आपराधिक अधिकार क्षेत्र न्यायनिर्णयः दाण्डिक अपीलीय सं 651/2012

राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के एस. बी. आपराधिक की पुनरीक्षण याचिका संख्या 597/2009 के 19.08.2010 के निर्णय और आदेश से।

अपीलकर्ता के लिए एम. आर. काला, शिवानी एम. लाल, अमित कुमार सिंह, उदय गुप्ता, एम. के. त्रिपाठी, प्रतीक्षा शर्मा, आर. सी. कौशिक।

पी. एस. नरसिम्हा, श्रीराम प्रभात, विष्णु शंकर जैन सुशील के. प्रतिवादीओं के लिए दुबे, प्रगति निखार, आर. गोपालकृष्णन।

न्यायालय का निर्णय ज्ञान सुधा मिश्रा, जे द्वारा दिया गया था।

1. राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा दिनांकित 19.08.2010 का निर्णय और आदेश जोधपुर में 2009 के एस. बी. सी. आर. आर. सं 597 में अपीलकर्ता ओम प्रकाश के कहने पर इस अपील को चुनौती दी गई है, जो 13 प्रतिशत वर्ष की एक निर्दोष लड़की का असहाय पिता है, जिसे कथित आरोपी-प्रतिवादी संख्या 2 विजय कुमार @भानवरु द्वारा बलात्कार का शिकार बनाया गया था, जिसे किशोर न्यायाधीश (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम 2000 के तहत सुरक्षा का लाभ उठाने की अनुमति दी गई है, हालांकि नीचे की अदालतें यह निष्कर्ष दर्ज नहीं कर सकीं कि वह वास्तव में एक किशोर था क्योंकि वह घटना की तारीख को 18 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं

कर पाया था। इसलिए यह विशेष अनुमति याचिका जिसमें देरी को माफ करने के बाद अनुमति दी गई है।

2. इस प्रकार अन्य बातों के साथ साथ साथ-साथ जिन प्रश्नों पर इस अपील में विचार करने की आवश्यकता है, वे हैंः-

(□) क्या प्रतिवादी/अभियुक्त, जिस पर भा.दं.सं. सी. की खंड 376 और अन्य संबद्ध खंडओं के तहत बलात्कार का अपराध करने का आरोप है, अभियुक्त जो पहले से ही भा.दं.सं. सी. की खंड 376 के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया जा चुका है, उसे किशोर न्यायाधीश (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2000 (जल्द ही 'किशोर न्यायाधीश अधिनियम' के रूप में संदर्भित) के तहत किशोर अदालत में मुकदमे के लिए भेजने के लिए एक किशोर को सुरक्षा का लाभ उठाने की अनुमति दी जा सकती है, हालांकि निचली अदालत और उच्च निचली अदालत इस तथ्य का निर्णायक निष्आदेश्ष दर्ज नहीं आदेश सके कि प्रतिवादी-अभियुक्त घटना की तारीख को 18 वर्ष से कम आयु का था?

(□□) क्या किशोर न्यायाधीश अधिनियम से संबंधित 'हितकारी विधान' का सिद्धांत और लाभ उन मामलों में लागू किया जा सकता है जहां बच्चे/अभियुक्त की आयु के निर्धारण के संबंध में दो विचार संभव थे और तथाकथित बच्चे को प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर किशोर नहीं ठहराया जा सकता था?

(□□□) यदि विद्या सम्बन्धी अभिलेख प्रमाण पत्र निर्णायक रूप से अभियुक्त की आयु साबित नहीं करते हैं, तो क्या किशोर की आयु निर्धारित करते समय चिकित्सा साक्ष्य और अन्य उपस्थित परिस्थितियों का कोई महत्व और सहायता होगी?

(□□□) यदि अभियुक्त की आयु को छिपाने के लिए विद्या सम्बन्धी अभिलेखों से संबंधित प्रमाण पत्र जानबूझआदेश रखे गए हैं और आयु के संबंध में चिकित्सा साक्ष्य

की प्रामाणिकता को चुनौती दी जा रही है तो क्या चिकित्सा साक्ष्य पर निर्भरता रखी जानी चाहिए?

3. किशोर न्यायाधीश अधिनियम को किशोर न्यायाधीशालय द्वारा बच्चों/किशोरों का मुकदमा चलाने के लिए एक अलग मंच या एक विशेष अदालत प्रदान करने के प्रशंसनीय उद्देश्य के साथ अधिनियमित किया गया था क्योंकि यह महसूस किया गया था कि बच्चे परिस्थितियों के बल पर अपचारी बन जाते हैं न कि पसंद से और इसलिए आपराधिक अपराध से जुड़े मामलों से निपटने और उनका मुकदमा चलाने के दौरान उनके साथ सावधानी और संवेदनशीलता के साथ व्यवहार करने की आवश्यकता होती है।लेकिन जब किसी अभियुक्त पर बलात्कार और हत्या या कोई अन्य गंभीर अपराध करने का आरोप लगाया जाता है, जब वह 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद बच्चा नहीं रह जाता है, लेकिन नाबालिग होने की स्पष्ट याचिका के तहत किशोर न्यायाधीश अधिनियम की सुरक्षा चाहता है, तो क्या ऐसे अभियुक्त को किशोर न्यायाधीशालय द्वारा मुकदमा चलाने की अनुमति दी जानी चाहिए या उसे आपराधिक अधिकार क्षेत्र के सक्षम न्यायाधीशालय में भेजा जाना चाहिए जहां अन्य वयस्क व्यक्तियों का मुकदमा आयोजित किया जाता है।

4. इस अपील में पहले जिन प्रश्नों का उल्लेख किया गया है, वे अभिलेख पर मौजूद सामग्री से सामने आए तथ्यों और परिस्थितियों के तहत उत्पन्न होते हैं, जिससे पता चलता है कि अपीलार्थी/शिकायतकर्ता ने दोपहर करीब एक बजे आई. डी. 2 पर एक लिखित रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी 13 साल की बेटी संध्या, जो माध्यमिक विद्यालय घेवाड़ा में नौवीं कक्षा की छात्रा है, को आरोपी भंवरु @विजय कुमार, जो जोगा राम का बेटा है, ने दोपहर करीब डेढ़ बजे आई. डी. 1 पर नीतू नाम की अपनी दोस्त द्वारा से स्कूल से बुलाया था। नीतू ने संध्या को बताया कि भंवरू बस स्टैंड के पास बोलेरो वाहन में था। संध्या ने स्कूल के अधिकारियों से अनुमति लेने के बाद स्कूल

छोड़ दिया और जब वह बस स्टैंड के पास पहुंची तो उसे बोलेरो वाहन नहीं मिला। इसलिए, उसने भानवरु को एक टेलीफोन कॉल किया जिसने उसे बताया कि वह बस स्टैंड के आगे तिवारी रोड पर खड़ा है। फिर उसने तिवारी रोड पर बोलेरो वाहन देखा, लेकिन उसे नीतू नहीं मिली और जब उसने नीतू के बारे में पूछताछ की, तो आरोपी भानवरु उर्फ जोगा राम के बेटे विजय कुमार ने उसे गुमराह किया और बताया कि नीतू शौचालय जाने के लिए नीचे उतर गई थी, जिसके बाद उसे वाहन में बैठाया गया, जिसे जबरन तिवारी की ओर ले जाया गया और 3 से 4 किलोमीटर की दूरी के बाद सुभाष बिश्नोई नाम के एक व्यक्ति को भी वाहन में बिठाया गया।इसके बाद वाहन को सड़क से दूर एक सुनसान जगह पर ले जाया गया, जहाँ भंवरू @विजय कुमार और सुभाष बिश्नोई ने उसके साथ बलात्कार किया।चूंकि पीड़ित लड़की/याचिकाकर्ता की बेटी ने विरोध किया और विरोध किया, इसलिए उसे पीटा गया, जिसके परिणामस्वरूप उसकी जांघ, हाथ और पीठ पर चोटें आईं। इसके बाद उसे चंदालिया गांव ले जाया गया और उसके साथ फिर से बलात्कार किया गया।भानवरु को तब एक फोन आया जिसके बाद भानवरु और सुभाष ने उसे गाँव घेवाड़ा के पास छोड़ दिया, लेकिन उसे धमकी दी कि अगर उसने इस घटना के बारे में किसी को बताया तो उसे मार दिया जाएगा।इसलिए, संध्या ने स्कूल में किसी को भी इस घटना के बारे में नहीं बताया, लेकिन घर पहुंचने पर, उसने अपनी माँ यानी अपीलकर्ता/शिकायतकर्ता की पत्नी को इसकी जानकारी दी, जिसने अपीलकर्ता को यह बात तब सुनाई जब वह जोधपुर से गाँव वापस आया। अपीलकर्ता घटना के परिणामों को ध्यान में रखते हुए तत्काल निर्णय नहीं ले सका और जोधपुर से अपने भाई पीयूष को बुलाया और फिर पी. एस. ओसियन के पास एक रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसके आधार पर भा.दं.सं. सी. की खंड 365,323 और 376 के तहत मामला दर्ज किया गया। 40/2007 दिनांकित 25.2.2007 जाँच के दौरान, आरोपी भानवरु @विजय कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तारी ज्ञापन में

उसका नाम विजय कुमार @भोग राम के बेटे भंवर लाल के रूप में उल्लेख किया गया और उसकी उम्र 19 वर्ष बताई गई है।जाँच पूरी होने के बाद, यह पाया गया कि भा.दं.सं. सी. की धारा 363,366,323 और 376 (2) (जी) के तहत आरोपी विजय कुमार उर्फ 19 वर्षीय जोगा राम जाट के बेटे भंवर लाल, 20 वर्षीय बगराम बिश्नोई के बेटे सुभाष और श्रीमती के खिलाफ अपराध किए गए। 27 वर्षीय मुकेश कंवर @मुगली @नीतू और इसलिए न्यायिक मजिस्ट्रेट, ओसियन के समक्ष आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया था।विजय कुमार उर्फ भंवर लाल और सुभाष को न्यायिक हिरासत में ले लिया गया।

5. इसके बाद आरोपी विजय कुमार उर्फ भंवर लाल की ओर से न्यायिक मजिस्ट्रेट, ओसियन के समक्ष एक आवेदन दायर किया गया जिसमें कहा गया कि वह एक किशोर अपराधी था और इसलिए उसे मुकदमे के लिए किशोर अदालत में भेजा जा सकता है।

6. उपरोक्त आवेदन पर संबंधित विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा 29.3.2007 पर दलीलें सुनी गईं और विद्वान मजिस्ट्रेट ने अपने दिनांकित 29.3.2007 आदेश द्वारा आवेदन को स्वीकार कर लिया, हालांकि लोक अभियोजक ने पुलिस जांच और चिकित्सा रिपोर्ट पर भरोसा करते हुए इस आवेदन का विरोध किया जिसमें आरोपी की आयु 19 वर्ष दर्ज की गई थी। आवेदन में, विजय कुमार की ओर से लिया गया रुख यह था कि स्कूल के रिकॉर्ड में उनकी जन्म तिथि 30.6.1990 थी।

7. हालाँकि, इस आवेदन की सामग्री से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि विजय कुमार की ओर से आवेदन में कोई विवाद नहीं उठाया गया था कि आरोपी विजय कुमार का नाम केवल विजय कुमार था न कि भंवर लाल। यह भी आग्रह नहीं किया गया कि

पुलिस के कागजात में आरोपी विजय कुमार का नाम गलत तरीके से विजय कुमार उर्फ भंवर लाल के रूप में उल्लिखित किया गया है और न ही जांच के दौरान यह कहा गया है कि आरोपी विजय कुमार उर्फ भंवर लाल के नाम पर गलत तरीके से मामला दर्ज किया गया था। इस विवाद को उठाए बिना, विजय कुमार उर्फ भंवर लाल का विद्या सम्बन्धी रिकॉर्ड पेश किया गया, जबकि शिकायतकर्ता के अनुसार तथ्यात्मक स्थिति यह है कि आरोपी का नाम भंवर लाल था जो सरकारी माध्यमिक विद्यालय जेलू गागड़ी (ओसियन) में दर्ज किया गया था जब उसने 18.12.1993 पर स्कूल में प्रवेश किया था और फिर 22.4.1996 पर उसका नाम स्कूल रजिस्टर में दर्ज किया गया था जिसमें उसकी जन्म तिथि 12.12.1988 के रूप में दर्ज की गई थी।

8. शिकायतकर्ता ने आरोपी विजय कुमार की उम्र का विरोध किया और यह प्रस्तुत किया गया कि आरोपी विजय कुमार को जेलू गागड़ी (ओसियन) में हरि ओम शिक्षा संस्थान के नाम से जाने जाने वाले किसी निजी स्कूल में विजय कुमार के रूप में परिवर्तित नाम के साथ दूसरी कक्षा में भर्ती कराया गया था और वहां जन्म तिथि का उल्लेख 30.6.1990 के रूप में किया गया था जो बाद के विद्या सम्बन्धी रिकॉर्ड में परिलक्षित हुआ था और उस आधार पर विजय कुमार के नाम के प्रवेश पत्र में जन्म तिथि 30.6.1990 का उल्लेख किया गया था ताकि उसे किशोर माना जा सके।

9. इसके बाद यह मामला अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक्ट नंबर 1) जोधपुर के समक्ष सत्र मामला संख्या 151/2007 के रूप में आई. डी. 1 पर आया। अभियुक्त के पिता श्री जोगा राम ने किशोर न्यायाधीश (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2000 की खंड 49 के तहत एक आवेदन दायर किया जिसमें कहा गया कि उनके बेटे की जन्म तिथि उनके स्कूल प्रशासन के रिकॉर्ड में 30.6.1990 थी और इसलिए, घटना की तारीख यानी 23.02.2007 पर, वह 18 वर्ष से कम उम्र का था। इस दिनांकित 3.10.2007 आवेदन पत्र में, आरोपी विजय कुमार के पिता जोगा

राम ने स्वयं तीन स्थानों पर शीर्षक, पैरा शुरू में और पहले भाग में अपने बेटे (आरोपी) का नाम विजय कुमार उर्फ भंवर लाल बताते हुए कहा था कि उनके बेटे का जन्म उनके घर पर 30.6.1990 पर हुआ था और उन्हें पहली बार हरि ओम शिक्षण संस्थान, जेलू गागड़ी, ओसियन नाम के स्कूल में दूसरी कक्षा में 1.9.1997 पर भर्ती कराया गया था और उनके बेटे ने इस स्कूल में दूसरी कक्षा से 1.9.1997 से 15.7.2007 तक पढ़ाई की थी और स्थानांतरण प्रमाण पत्र दिनांक 4.7.2007 संलग्न किया गया था।उक्त आवेदन पत्र पर आरोपी विजय कुमार के पिता के रूप में जोगा राम ने हस्ताक्षर किए थे, जिस पर मुहर के साथ प्रधानाध्यापक के हस्ताक्षर भी थे। स्थानांतरण प्रमाणपत्र में कुछ अन्य तथ्यों के साथ आरोपी की जन्म तिथि भी बताई गई थी ताकि यह आदेश किया जा सके कि विजय कुमार की आयु घटना की तारीख को 18 वर्ष से कम थी।लेकिन उन्होंने कहीं भी यह नहीं कहा था कि उनका एक और बेटा है जिसका नाम भानवरु है जिसकी मृत्यु 1995 में हुई थी और जिसकी जन्म तिथि 12.12.1988 थी।उन्होंने यह स्थापित करने का प्रयास किया कि आरोपी विजय कुमार जोगा राम का छोटा बेटा है और बड़े बेटे भानवरु की मृत्यु वर्ष 1995 में हुई थी और यह वही था जिसकी जन्म तिथि 1988 थी। इस प्रकार उन्होंने कहा कि विजय कुमार का जन्म वास्तव में वर्ष 1990 में हुआ था और उनका नाम भानवरु नहीं बल्कि केवल विजय कुमार था।कहानी के इस हिस्से को आरोपी जोगा राम के पिता ने बाद के चरण में स्थापित किया था जब सबूत पेश किए गए थे।

10. अभियुक्त विजय कुमार की ओर से दायर आवेदन को शिकायतकर्ता ने चुनौती दी थी और दोनों पक्षों ने अपनी-अपनी याचिका के समर्थन में साक्ष्य का नेतृत्व किया था। शिकायतकर्ता का विशिष्ट मामला यह था कि भंवरु लाल और विजय कुमार वास्तव में एक ही व्यक्ति हैं और जोगा राम ने एक कहानी रची है कि उनका भंवर लाल नाम का एक और बेटा था जिसकी जन्म तिथि 12.12.1988 थी और जिसकी बाद 1995

में मृत्यु हो गई। शिकायतकर्ता ने कहा कि आरोपी के पिता के बयान के अनुसार यदि मृतक का बेटा भंवर लाल 24.2.1996 तक स्कूल में बना रहा, तो यह असंभव था क्योंकि कहा जाता है कि उसकी मृत्यु 1995 में ही हो गई थी। शिकायतकर्ता के अनुसार विजय कुमार और भंवर लाल एक ही व्यक्ति के नाम हैं जिन्होंने वर्ष 2007 में बलात्कार का अपराध किया था और अभियुक्त द्वारा बचाव पक्ष लिया गया था। यह केवल किशोर न्यायाधीश अधिनियम का अनुचित लाभ उठाने के लिए एक मनगढ़ंत कहानी थी।

11. मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य पर विचार करने के बाद, सत्र न्यायालय ने स्पष्ट रूप से निष्कर्ष निकाला कि इस मामले में अभियुक्त की उम्र के संबंध में रिकॉर्ड पर आए साक्ष्य को ध्यान में रखते हुए कोई निश्चित स्पष्ट और निर्णायक दृष्टिकोण संभव नहीं है और दोनों विचार स्पष्ट रूप से स्थापित हैं और इसलिए, जो दृष्टिकोण अभियुक्त के पक्ष में है, उसे लिया जाता है और अभियुक्त को किशोर माना जाता है। आरोपी विजय कुमार को तदनुसार किशोर घोषित किया गया और उसे मुकदमे के लिए किशोर न्यायाधीश बोर्ड को भेजने का निर्देश दिया गया।यह आदेश अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक्ट नंबर 1) जोधपुर द्वारा सत्र मामला संख्या 151/2007 में 16.5.2009 पर पारित किया गया था।

12. इसके बाद शिकायतकर्ता-अपीलार्थी ने उच्च न्यायालय के समक्ष पुनरीक्षण याचिका दायर करके प्रत्यर्थी विजय कुमार को किशोर ठहराते हुए अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के आदेश पर हमला किया।पुनरीक्षण की सुनवाई करने वाले विद्वान न्यायाधीश ने कहा कि विजय कुमार @भानवरु की उम्र और पहचान के संबंध में बहुत सारे विरोधाभासी सबूत सामने आए हैं और आरोपी विजय कुमार @भानवरु की जन्म तिथि के संबंध में बहुत भ्रम पैदा किया गया है।लेकिन विद्वान एकल न्यायाधीश को यह कहते हुए खुशी हुई कि अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने सही परिप्रेक्ष्य में साक्ष्य की सराहना

की थी और प्रतिवादी नंबर 2 विजय कुमार उर्फ भानवरु को किशोर अपराधी घोषित करने में उनकी कोई गलती नहीं पाई गई।इसलिए, उन्हें मुकदमे के लिए किशोर न्यायाधीश बोर्ड के पास भेजा गया है। कोई हस्तक्षेप नहीं करता है।विद्वान एकल न्यायाधीश ने परिणामस्वरूप उस पुनरीक्षण याचिका को खारिज कर दिया जिसके खिलाफ शिकायतकर्ता ने यह विशेष अनुमति याचिका (सी. आर. एल.) नं. 2411/2011 दायर की थी। जिसने छुट्टी देने के बाद इस अपील को जन्म दिया है।

13. निचली अदालतों के आदेशों को स्वीकार करते हुए, अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने सुनवाई के दौरान अनिवार्य रूप से दो गुना प्रस्तुतियाँ दी हैं। उन्होंने शुरू में कहा था कि विजय कुमार उपनाम भंवर लाल, जोगा राम का बेटा वही व्यक्ति है और विजय कुमार भंवर लाल का बदला हुआ नाम है जिसकी सही जन्म तिथि 12.12.1988 है न कि 30.6.1990 जैसा कि आरोपी के पिता जोगा राम ने कहा है। इसलिए, विजय कुमार उर्फ भंवर लाल अपराध करने की तारीख को किशोर नहीं था।

14. इस याचिका को साबित आदेशने के लिए, अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि अभियुक्त के पिता जोगा राम द्वारा किशोर न्याय अधिनियम की खंड 49 के तहत अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के समक्ष दायर आवेदन में, उन्होंने कहीं भी उल्लेख नहीं किया है कि उनके विजय कुमार और भंवर लाल नाम के दो बेटे थे और भंवर लाल की मृत्यु 1995 में हुई थी, जिनकी जन्म तिथि 12.12.1988 थी और उनके दूसरे बेटे विजय कुमार की जन्म तिथि 30.6.1990 थी।वास्तव में, उन्होंने स्वयं आवेदन में एक से अधिक स्थानों पर अपने बेटे का नाम विजय कुमार उर्फ भानवरु के रूप में उल्लेख किया था और बाद में एक कहानी रखी कि उनके दो बेटे थे।, भंवर लाल और विजय कुमार, और भंवर लाल जिनकी जन्म तिथि 12.12.1988 थी, उनका वर्ष 1995 में निधन हो चुका था।

15. अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने आगे तर्क दिया कि किशोर न्याय अधिनियम को प्रदत्त परोपकारी विधान के सिद्धांत का लाभ वर्तमान मामले में लागू नहीं किया जा सकता है क्योंकि नीचे दी गई अदालतें-विशेष रूप से तथ्य की अदालत जो अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक नंबर 1) जोधपुर ने प्रतिवादी-अभियुक्त की जन्म तिथि के संबंध में एक स्पष्ट निष्कर्ष दर्ज नहीं किया और उपरोक्त सिद्धांत केवल उस मामले में लागू किया जा सकता है जहां अभियुक्त को स्पष्ट रूप से किशोर माना जाता है ताकि उसे किशोर अदालत द्वारा मुकदमे के लिए भेजा जा सके या कथित किशोर अभियुक्त द्वारा किसी अन्य लाभ का दावा किया जा सके।अपीलकर्ता के वकील ने एन. ए. डब्ल्यू.-3-मेडिकल ज्यूरिस्ट के साक्ष्य पर भरोसा किया है, जिन्होंने अभियुक्त का अस्थिकरण परीक्षण किया और अदालत के समक्ष राय दी कि अभियुक्त की आयु 19 वर्ष थी और एन. ए. डब्ल्यू.-1 रेडियोलॉजी में सहायक प्रोफेसर का बयान जिसने अदालत के समक्ष राय दी थी। 23.11.2007 पर कि एक्स-रे फिल्मों के आधार पर, अभियुक्त की आयु 18 वर्ष से अधिक और 20 वर्ष से कम है।

16. अभियुक्त-प्रत्यर्थी के विद्वान वकील ने अपनी ओर से तर्क दिया कि चिकित्सा राय केवल तभी ली जा सकती है जब मैट्रिक या समकक्ष प्रमाण पत्र या स्कूल से जन्म प्रमाण पत्र उपलब्ध न हो और चूंकि वर्तमान मामले में स्कूल रिकॉर्ड से आरोपी का प्रवेश प्रमाण पत्र उपलब्ध है जिसमें जन्म तिथि 30.6.1990 बताई गई है, इसलिए स्कूल प्रमाण पत्र को चिकित्सा राय पर हावी होने की अनुमति दी जानी चाहिए।

17. हम प्रत्यर्थी के लिए विद्वान अधिवक्ता के उपरोक्त तर्क की सराहना और प्रतिग्रहण करना करने में असमर्थ हैं क्योंकि अभियुक्त की उम्र केवल स्कूल रिकॉर्ड के आधार पर साबित नहीं की जा सकी क्योंकि नीचे की अदालतें अपनी जांच के बावजूद इस तथ्य का निष्कर्ष दर्ज नहीं कर सकीं कि अभियुक्त वास्तव में घटना की तारीख को

नाबालिग था।इसलिए, ऐसी स्थिति में जब स्कूल रिकॉर्ड स्वयं अस्पष्टता से मुक्त नहीं है और निर्णायक रूप से अभियुक्त की अल्पमत को साबित करता है, तो चिकित्सा राय को अनदेखा करने या बिना किसी परिणाम के माने जाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।इस संदर्भ में अभियुक्त का अस्थिकरण परीक्षण करने वाले चिकित्सा न्यायविद एन. ए. डब्ल्यू.-3 डॉ. जगदीश जुगटावत का बयान और अदालत के समक्ष यह राय महत्वपूर्ण है कि अभियुक्त की आयु 19 वर्ष थी क्योंकि इसमें विशेष रूप से कहा गया है कि अपराध करने की तिथि पर अभियुक्त किशोर नहीं था।एनएडब्ल्यू-1 डॉ. सी. आर. अग्रवाल, सहायक का बयान रेडियोलॉजी के प्रोफेसर को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता क्योंकि उनकी राय थी कि एक्स-रे फिल्मों के आधार पर आरोपी की उम्र 18 वर्ष से अधिक और 20 वर्ष से कम आयु का हो।इस प्रकार, ऐसी परिस्थिति में जहां निचली निचली अदालत स्वयं आरोपी की उम्र के संबंध में एक निर्णायक निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकी, एक्स-रे और ऑसिफिकेशन परीक्षण के आधार पर चिकित्सा विशेषज्ञों की राय को स्कूल के रिकॉर्ड के आधार पर अस्थिर साक्ष्य और आरोपी के पिता द्वारा स्थापित एक कहानी के आधार पर परिस्थितिजन्य निष्कर्ष की याचिका पर प्राथमिकता देनी होगी, जो प्रथमदृष्टया एक मुर्गा और बैल की कहानी है।

18. इसमें कोई संदेह नहीं है कि यदि किशोर अभियुक्त के पक्ष में कोई स्पष्ट और स्पष्ट मामला है कि वह घटना की तारीख को 18 वर्ष से कम उम्र का नाबालिग था और दस्तावेजी साक्ष्य कम से कम प्रथमदृष्टया यह साबित करते हैं, तो वह किशोर न्यायाधीश अधिनियम के तहत इस विशेष संरक्षण का हकदार होगा। लेकिन जब कोई अभियुक्त कोई गंभीर और जघन्य अपराध करता है और उसके बाद नाबालिग होने की आड़ में वैधानिक शरण लेने का प्रयास करता है, तो यह दर्ज करते समय कि क्या कोई अभियुक्त किशोर है या नहीं, एक आकस्मिक या घुड़सवार दृष्टिकोण की अनुमति नहीं दी जा सकती है क्योंकि अदालतों को न्यायाधीश के प्रशासन को सौंपे गए संस्थान में आम

आदमी के विश्वास की रक्षा करने के उद्देश्य से अपने कर्तव्यों का पालन करने का आदेश दिया जाता है।इसलिए, जबकि अदालतों को यौन उत्पीड़न, बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, हत्या और अन्य अपराधों जैसे गंभीर प्रकृति के मामलों में शामिल किशोर से निपटने में संवेदनशील होना चाहिए, आरोपी को खुद को नाबालिग साबित करने का प्रयास करके वैधानिक संरक्षण का दुरुपयोग करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, जब उसका अल्पसंख्यक होने के उसके दावे के बारे में दस्तावेजी साक्ष्य एक उचित संदेह को जन्म देता है।ऐसी परिस्थिति में, वैज्ञानिक जांच के आधार पर चिकित्सा साक्ष्य को उचित महत्व देना होगा और स्कूल प्रशासन के अभिलेखों के आधार पर साक्ष्य पर वरीयता जो अभियुक्त की उम्र के बारे में परिकल्पना और अटकलों को जन्म देती है। फिर भी मामला यदि आरोप लगाया जाता है कि विद्या सम्बन्धी प्रमाणपत्र और स्कूल रिकॉर्ड जानबूझकर गलत उद्देश्य से रखे गए हैं और अभियोजन पक्ष द्वारा चिकित्सा साक्ष्य की प्रामाणिकता को चुनौती दी जाती है तो यह एक अलग आधार पर खड़ा होगा।

19. तत्काल मामले में, आरोपी विजय कुमार पर एक ऐसा अपराध करने का आरोप है जो नैतिक विवेक के खिलाफ है क्योंकि उसने अपने साथी की सहायता से साजिश रचकर अपनी वासना को संतुष्ट करने के लिए साढ़े 13 साल की एक लड़की को चुना। सुभाष, जो पहले से ही दोषी ठहराया जा चुका है और उसके बाद आरोपी ने इस दलील के तहत सुरक्षा मांगने का प्रयास किया है कि उसने अपनी बेगुनाही के कारण ऐसा कार्य किया है, इसके निहितार्थ को समझे बिना जिसमें उसके पिता जोगा राम स्पष्ट रूप से एक कहानी में शामिल करने का प्रयास करके सहायता कर रहे हैं कि वह घटना की तारीख को नाबालिग था, जो विश्वास के योग्य निर्णायक साक्ष्य पर आधारित नहीं है, बल्कि एक भ्रमित कहानी के साथ-साथ साक्ष्य की अस्थिर और नाजुक प्रकृति पर आधारित है जो शायद ही विश्वास को प्रेरित करता है।यह नजरअंदाज करना कठिन

है कि जब अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य की सावधानीपूर्वक जांच के बावजूद एक निर्णायक निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सके कि वह स्पष्ट रूप से घटना की तारीख को 18 वर्ष से कम उम्र का किशोर था, तो किस तर्क और तर्क से उसे किशोर न्याय अधिनियम के आधार पर परोपकारी विधान के सिद्धांत का लाभ मिलना चाहिए, यह समझना मुश्किल है क्योंकि यह स्पष्ट रूप से इस सिद्धांत के गलत अनुप्रयोग में परिणाम देता है और इस प्रकार हम अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के तर्क में पर्याप्त बल पाते हैं कि परोपकारी कानून के सिद्धांत का लाभ केवल उन अपराधियों के पक्ष में लागू किया जा सकता है जिन्हें निस्संदेह एक किशोर माना गया है, जो कथित की उम्र के बारे में अटकलों की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ते हैं।

20. इसलिए हम इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकते कि निचली अदालत के साथ-साथ उच्च निचली अदालत भी विवादित आदेश पारित करते समय किसी भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सका कि क्या आरोपी घटना की तारीख को बड़ा था या नाबालिग था और फिर भी एक ऐसे आरोपी को परोपकारी कानून के सिद्धांत का लाभ दिया, जिसकी अल्पमत की याचिका कि वह 18 वर्ष से कम आयु का था, संदेह में था।ऐसी स्थिति में, किशोरता की याचिका के समर्थन में एक विश्वसनीय और ठोस सबूत के लिए जोर देकर न्यायाधीश के तराजू को एक समान आधार पर रखने की आवश्यकता होती है, विशेष रूप से जब पीड़ित भी नाबालिग था।

21. इस प्रकार किशोर न्यायाधीश अधिनियम से जुडे परोपकारी विधान के सिद्धांत का लाभ केवल ऐसे मामलों पर लागू होगा जिसमें अभियुक्त को कम से कम अपने अल्पसंख्यक के बारे में प्रथमदृष्टया साक्ष्य के आधार पर किशोर माना जाता है, जो कथित अभियुक्त की उम्र के संबंध में दो विचारों की संभावनाओं के लाभ के रूप में है जो गंभीर और गंभीर अपराध में शामिल है जो उसने किया है और इसे निर्दोषता के बजाय अपनी मानसिक परिपक्वता को दर्शाते हुए एक सुनियोजित तरीके से लागू किया

है जो यह दर्शाता है कि उसकी किशोरता की याचिका कानून के हथियारों को चकमा देने या धोखा देने के लिए ढाल की प्रकृति में अधिक है, उसे उसके बचाव में आने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।इसलिए यदि किशोरावस्था या यह तथ्य कि उसने विवेक की आयु प्राप्त नहीं की थी ताकि वह अपने जघन्य कृत्य के परिणाम को समझ सके, मुक्त नहीं है। अस्पष्टता या संदेह के कारण, उक्त याचिका को केवल संदिग्ध स्कूल प्रवेश रिकॉर्ड पर उठाए जाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है और यदि यह संदिग्ध है, तो आरोपी की उम्र का निर्धारण करते समय चिकित्सा साक्ष्य को उचित महत्व देना होगा।

22. इस मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए हमने देखा है कि अभियुक्त की ओर से दिए गए साक्ष्य के बावजूद निचली निचली अदालत खुद इस बात से संतुष्ट नहीं थी कि अभियुक्त नाबालिग था क्योंकि प्रतिवादी-अभियुक्त द्वारा भरोसा किए गए किसी भी स्कूल रिकॉर्ड को संदेह से मुक्त नहीं माना जा सकता था ताकि अभियुक्त की सही जन्म तिथि तय करने के उद्देश्य से एक तार्किक और कानूनी आधार बनाया जा सके जो यह दर्शाता है कि अभियुक्त घटना की तारीख को नाबालिग/किशोर था।इस न्यायालय ने रामदेव चौहान @राज नाथ बनाम असम राज्य के मामले सहित कई फैसलों में, (2001) 5 एस. सी. सी. 714 में इसी तरह की परिस्थिति से निपटने की रिपोर्ट में कहा था कि जो हमने कहा है उसमें वजन और ताकत जोड़ता है जिसे यहां निम्नानुसार उद्धृत किया गया हैः-

"यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता किशोर न्यायाधीश अधिनियम या बाल अधिनियम के अर्थ में न तो बच्चा था और न ही बच्चे होने की उम्र के करीब था। अपराध के समय वह मेजर साबित होता है।इसमें कोई संदेह नहीं है कि अदालत के दिमाग में एक उचित संदेह पैदा होता है, क्योंकि आरोपी उसे कम सजा का लाभ देता है, यह सच है कि आरोपी उन्होंने अपनी उम्र के संबंध में एक स्मोक स्क्रीन बनाने की कोशिश की। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि इस तरह के प्रयास केवल उनकी वास्तविक उम्र को

छिपाने के लिए किए गए थे और अदालत के मन में कोई संदेह पैदा करने के लिए नहीं। ढीली सजाओं का लाभ उठाकर कल्पनाशील और मनगढ़ंत आधारों का सहारा लेकर न्यायिक प्रणाली को फिरौती लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती है कुछ गवाहों के साक्ष्य में विशेष रूप से विशेष अनुमति याचिका के चरण में उपस्थित होना। कानून निर्णयों की अंतिमता पर जोर देता है और न्यायिक प्रणाली को मजबूत करने से अधिक संबंधित है। न्यायाधीश के प्रशासन को सौंपे गए संस्थान में आम आदमी के विश्वास को मजबूत करने के उद्देश्य से अदालतों को अपने कर्तव्यों का पालन करने का आदेश दिया जाता है।कोई भी प्रयास जो व्यवस्था को कमजोर करता है और न्यायाधीश व्यवस्था में आम आदमी के विश्वास को हिलाता है, उसे हतोत्साहित किया जाना चाहिए।

उपरोक्त टिप्पणियाँ निस्संदेह इस न्यायालय के विद्वान न्यायाधीशों द्वारा किशोर होने का दावा करने वाले अभियुक्त पर मृत्युदंड लगाने पर विचार करते समय दर्ज की गई थीं, फिर भी उसमें व्यक्त किए गए विचार स्पष्ट रूप से एक ऐसे मुद्दे को हल करने के लिए वजन बढ़ाते हैं जहां अदालत स्पष्ट रूप से एक निष्कर्ष निकालने की स्थिति में नहीं है जिसमें अभियुक्त या उसके अभिभावक द्वारा एक किशोर को उपलब्ध लाभ का दावा करने का प्रयास किया जाता है जो तथाकथित किशोर अभियुक्त के प्रति उदार व्यवहार के लिए अदालत पर सहानुभूति प्राप्त करने और प्रभाव डालने का प्रयास हो सकता है, जो वास्तव में घटना की तारीख को एक वयस्क था।

23. हालाँकि, हम दोहराते हैं कि हमें गलत नहीं समझा जा सकता है ताकि यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि भले ही कोई आरोपी अपराध करने की तारीख को स्पष्ट रूप से 18 वर्ष की आयु से कम हो। अपराध, किशोर न्यायाधीश अधिनियम के तहत एक किशोर को उपलब्ध संरक्षण या उपचार प्रदान नहीं किया जाना चाहिए यदि उसकी उम्र के बारे में कोई विवाद उठाया गया था, लेकिन अंततः साक्ष्य की जांच पर हल किया गया था।जिस बात पर जोर दिया जाना चाहिए वह यह है कि जहां अदालतें

रिकॉर्ड पर उपलब्ध साक्ष्य के बावजूद स्पष्ट रूप से निष्आदेश नहीं निकाल सकती हैं कि आरोपी एक किशोर है या उक्त याचिका केवल एक धुंध या स्मोकस्क्रीन बनाने के लिए उठाई गई प्रतीत होती है ताकि उसकी वास्तविक उम्र को छिपाया जा सके। अभियुक्त को उसके अल्पमत के अनुरोध पर, प्रयास को सफल होने की अनुमति नहीं दी जा सकती है ताकि न्यायाधीश के कारण को नष्ट किया जा सके या धोखा दिया जा सके।अल्पमत की याचिका और बहाना की याचिका के बीच समानांतर बताते हुए, यह कहना सार्थक हो सकता है कि आपराधिक मामलों का सामना करना असामान्य नहीं है जिसमें एक आरोपी बहाना की याचिका के तहत बहाना लेने का प्रयास करता है जिसे पहली बार में उठाया जाना है, लेकिन अपराध की सुनवाई करने वाली अदालत द्वारा सबूत के सख्त सबूत के अधीन होना पड़ता है और केवल इस हितकारी सिद्धांत की सहायता से सबूत की कमी के बावजूद हल्के में अनुमति नहीं दी जा सकती है कि एक निर्दोष व्यक्ति को बहाना की याचिका के बावजूद दोषसिद्धि का आदेश दर्ज करके अन्याय का सामना नहीं करना पड़ सकता है।इसी तरह, यदि किसी अभियुक्त का आचरण या अपराध करने का तरीका और तरीका अपराध करने वाले अभियुक्त की एक बुरी और सुनियोजित साजिश का संकेत देता है, जो एक निर्दोष बच्चे की तुलना में एक अभियुक्त के परिपक्व कौशल की ओर अधिक संकेत करता है, तो अभियुक्त की उम्र के समर्थन में विश्वसनीय दस्तावेजी साक्ष्य की अनुपस्थिति में में, चिकित्सा साक्ष्य यह दर्शाता है कि अभियुक्त एक वयस्क था। किशोर न्यायाधीश अधिनियम जैसे परोपकारी कानून के सिद्धांत की शरण लेते हुए, न्यायाधीश के पाठ्यक्रम को बाधित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है क्योंकि किशोर न्यायाधीश अधिनियम का वैधानिक संरक्षण उन नाबालिगों के लिए है जो निर्दोष कानून तोड़ने वाले हैं और उन पर परिपक्व दिमाग का आरोप नहीं है जो अल्पसंख्यक की याचिका का उपयोग करते हैं उसके द्वारा किए गए अपराध की सजा से खुद को बचाने के लिए एक चाल या ढाल के रूप में। किशोर

न्यायाधीश अधिनियम के तहत परोपकारी कानून का लाभ स्पष्ट रूप से एक वास्तविक बाल आरोपी/किशोर को सुरक्षा प्रदान करेगा जो अदालत को इस दुविधा में नहीं डालता है कि वह नाबालिग है या नहीं, अपनी अल्पमत की याचिका के समर्थन में सबूत पेश करके, लेकिन इसकी अनुपस्थिति में में, केवल स्कूल प्रवेश रजिस्टर जैसे अस्थिर साक्ष्य पर भरोसा किया जाता है जो साबित नहीं होता है या अनुमानों के आधार पर मौखिक साक्ष्य जो आगे अस्पष्टता की ओर ले जाता है, चिकित्सा की वरीयता में भरोसा नहीं किया जा सकता है! अभियुक्त की आयु का आकलन करने के लिए साक्ष्य।

24. चिकित्सा साक्ष्य की प्रासंगिकता और मूल्य पर विचार करते हुए, उम्र के बारे में डॉक्टर का अनुमान हालांकि सबूत के लिए एक मजबूत पदार्थ नहीं है क्योंकि यह केवल एक राय है, ऑसिफिकेशन और रेडियोलॉजिकल परीक्षा जैसे वैज्ञानिक चिकित्सा परीक्षण पर आधारित ऐसी राय को कथित किशोर आरोपी की उम्र का निर्धारण करते समय एक मजबूत साक्ष्य के रूप में माना जाना चाहिए।रामदेव चौहान बनाम असम राज्य (ऊपर) के मामले में, विद्वान न्यायाधीशों ने

इस मुद्दे के निर्धारण के लिए एक अंतर्दृष्टि जोड़ी गई जब इसे निम्नानुसार दर्ज किया गयाः-

"बेशक उम्र के बारे में डॉक्टर का अनुमान सबूत के लिए एक मजबूत विकल्प नहीं है क्योंकि यह केवल उसकी राय है।लेकिन किसी विशेषज्ञ की इस तरह की राय को उस दायरे में दरकिनार नहीं किया जा सकता है जहां अदालत यह पता लगाने के लिए अंधेरे में टकटकी लगाती है कि उसे संवैधानिक संरक्षण देने के उद्देश्य से एक नागरिक की उम्र क्या होगी।अन्य स्वीकार्य सामग्री की अनुपस्थिति में में, यदि ऐसी राय उसकी उम्र की सीमा के बारे में एक उचित संभावना की ओर इशारा करती है, तो निश्चित रूप से इस पर विचार किया जाना चाहिए।

हालाँकि, स्थिति अलग होगी यदि विद्या सम्बन्धी रिकॉर्ड कथित रूप से कथित किशोर की उम्र को छिपाने के लिए जानबूझकर रखे गए हैं और अभियोजन पक्ष के कहने पर चिकित्सा साक्ष्य की प्रामाणिकता को चुनौती दी गई है।उस स्थिति में, चिकित्सा साक्ष्य पर भरोसा किया जाना चाहिए या नहीं, यह स्पष्ट रूप से प्रतिद्वंद्वी दलों के नेतृत्व में साक्ष्य के मूल्य पर निर्भर करेगा।

25. मामले के प्रचलित तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर उपरोक्त चर्चा और विश्लेषण को देखते हुए, हमारा विचार है कि प्रत्यर्थी संख्या 2 विजय कुमार और उनके पिता यह साबित करने में विफल रहे हैं कि प्रत्यर्थी संख्या 2 अपराध के समय नाबालिग था और इसलिए उसे किशोर न्यायाधीश अधिनियम का लाभ नहीं दिया जा सकता था, जो निस्संदेह एक परोपकारी कानून है, लेकिन एक आरोपी द्वारा इसका लाभ उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, जिसने किशोरता की याचिका को केवल अपनी वास्तविक उम्र को छिपाने के प्रयास के रूप में लिया है ताकि निचली अदालतों के मन में संदेह पैदा किया जा सके, जिन्होंने केवल परोपकारी कानून के सिद्धांत को अपनाकर उसे किशोर का लाभ देना उचित समझा, लेकिन इसके महत्वपूर्ण निहितार्थ को छोड़ दिया है कि हालांकि किशोरहम यह देखने के लिए विवश हैं कि यदि अभिलेख पर साक्ष्य और अन्य सामग्री यह साबित करने में विफल रहती है कि आरोपी अपराध करने के समय किशोर था तो इसे हतोत्साहित करना होगा।किशोर न्यायाधीश अधिनियम, जो निश्चित रूप से एक आरोपी बच्चे के साथ देखभाल और संवेदनशीलता के साथ व्यवहार करने के लिए है, जो उसे समाज की मुख्यधारा में सुधार करने और बसने का मौका देता है, इसे जघन्य अपराधों के मुकदमे और उपचार का संचालन करते समय न्यायाधीश के पाठ्यक्रम को धोखा देने के लिए एक चाल के रूप में इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।इसे स्पष्ट रूप से न्यायाधीश व्यवस्था को कमजोर करने के प्रयास के रूप में माना जाएगा और इसलिए इसे प्रोत्साहित नहीं किया

जा सकता है।

26. इसलिए हम उच्च न्यायालय और नीचे की अदालतों द्वारा पारित निर्णय और आदेश को दरकिनार करना उचित और उचित समझते हैं और इस प्रकार इस अपील की अनुमति देते हैं।नतीजतन, आरोपी विजय कुमार, पुत्र जोगा राम को सक्षम अधिकार क्षेत्र की अदालत के समक्ष मुकदमे के लिए भेजा जाएगा, जिसमें मुकदमा लंबित है, न कि किशोर अदालत में, जैसा कि उसने अनुरोध किया है। हम उसी के अनुसार आदेश देते हैं।

बी. बी. बी. अपील की अनुमति दी गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।